देहरादून (उत्तराखण्ड)
शुक्रवार 30.01.2026
समय 07.20

मुख्य समाचार :–

- अंतरराष्ट्रीय विमानन सम्मेलन 'विंग्स इंडिया 2026' में उत्तराखंड को एविएशन इकोसिस्टम के संवर्धन के लिए सर्वश्रेष्ठ राज्य का प्रतिष्ठित सम्मान प्रदान किया गया।
- मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सचिवालय में कृषि, पशुपालन, पर्यटन और उद्योग विभागों की योजनाओं की समीक्षा कर रोजगार और स्वरोजगार से जुड़े प्रयासों को तेज करने के निर्देश दिए।
- केंद्र सरकार ने समग्र शिक्षा के अंतर्गत राज्य के 544 नए विद्यालयों में व्यावसायिक शिक्षा संचालित करने की अनुमति दी।
- और, प्रदेश के सभी सरकारी अस्पतालों को सरकारी अस्पताल सूचना प्रबंधन प्रणाली–एच.आई.एम. एस, को प्राथमिकता के साथ लागू करने के निर्देश।

सम्मान

अंतरराष्ट्रीय विमानन सम्मेलन एवं प्रदर्शनी 'विंग्स इंडिया 2026' में उत्तराखंड को 'एविएशन इकोसिस्टम के संवर्धन के लिये सर्वश्रेष्ठ राज्य' के प्रतिष्ठित सम्मान से सम्मानित किया गया है। यह पुरस्कार नागरिक उड्डयन क्षेत्र में राज्य सरकार के प्रयासों, नीतिगत समर्थन और विमानन व्यवस्था को मजबूत करने के लिए दिया गया।

हैदराबाद के बेगमपेट एयरपोर्ट पर आयोजित कार्यक्रम में केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री किंजरापु राममोहन नायडू और नागरिक उड्डयन मंत्रालय के सचिव समीर कुमार सिन्हा ने उत्तराखंड को यह सम्मान प्रदान किया। कार्यक्रम में उत्तराखंड नागरिक उड्डयन विकास प्राधिकरण के सचिव सचिन कुर्वे, मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ. आशीष चौहान सहित अन्य अधिकारी मौजूद रहे।

विंग्स इंडिया 2026 देश का प्रमुख विमानन मंच है, जिसमें नीति निर्माता, उद्योग विशेषज्ञ और निवेशक शामिल होते हैं। इस मंच पर उत्तराखंड को मिला यह सम्मान राज्य के लिए उपलब्धि के रूप में देखा जा रहा है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इसे राज्य की विमानन नीति, बेहतर प्रशासनिक समन्वय और हवाई संपर्क को मजबूत करने की दिशा में किए गए प्रयासों का परिणाम बताया है।

निर्देश

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सचिवालय में कृषि, पशुपालन, पर्यटन और उद्योग से जुड़ी योजनाओं की समीक्षा करते हुए रोजगार और स्वरोजगार से जुड़े प्रयासों को तेज करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि सरकार की योजनाओं के माध्यम से अधिक से अधिक लोगों को रोजगार और स्वरोजगार से जोड़ा जाए तथा पात्र लोगों को योजनाओं का समय पर पूरा लाभ देना सुनिश्चित किया जाए।

मुख्यमंत्री ने युवाओं के कौशल विकास पर विशेष ध्यान देने और स्वरोजगार के लिए अधिक अवसर उपलब्ध कराने को कहा। उन्होंने 'जन–जन की सरकार, जन–जन के द्वार' अभियान के तहत लोगों तक योजनाओं की पूरी जानकारी पहुंचाने और आवंटित बजट से अपेक्षित परिणाम सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। साथ ही उच्च स्तरीय बैठकों के कार्यवृत्त उन्नति पोर्टल पर अनिवार्य रूप से अपलोड करने को कहा।

बैठक में सेब की अति सघन बागवानी योजना की समीक्षा करते हुए मुख्यमंत्री ने किसानों को प्रोत्साहित करने, लक्ष्यों को समय पर पूरा करने और किसानों से जुड़े देयकों का भुगतान समय से सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने किसानों को बेहतर मूल्य दिलाने के लिए कीवी उत्पादन को बढ़ावा देने पर भी जोर दिया। शहद उत्पादन की संभावनाओं को देखते हुए 'हनी मिशन' के तहत प्रभावी प्रयास करने और ऑर्गेनिक सर्टिफिकेशन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए।

समीक्षा

राज्य में आवास और शहरी विकास से जुड़ी योजनाओं को नई दिशा देने के उद्देश्य से हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट कॉरपोरेशन–हडको के सहयोग से संचालित योजनाओं की समीक्षा की गई। सचिव आवास डॉ. आर. राजेश कुमार की अध्यक्षता में हुई बैठक में प्रधानमंत्री आवास योजना, रेंटल हाउसिंग योजना और भविष्य की शहरी विकास रणनीतियों पर चर्चा हुई।

बैठक का मुख्य फोकस आर्थिक रूप से कमजोर और निम्न आय वर्ग के लिए सस्ते, सुरक्षित और टिकाऊ आवास उपलब्ध कराने पर रहा। इसके साथ ही साल 2050 तक की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए राज्य की भौगोलिक और सामाजिक परिस्थितियों के अनुरूप दीर्घकालिक कार्ययोजना तैयार करने पर सहमति बनी। बैठक में यह भी तय किया गया कि नए नगरों और टाउनशिप के विकास में हडको राज्य सरकार को तकनीकी और वित्तीय सहयोग देगा। शहरी क्षेत्रों के साथ–साथ ग्रामीण और पर्वतीय इलाकों में भी सुनियोजित आवास विकास पर जोर दिया जाएगा, ताकि संतुलित विकास सुनिश्चित किया जा सके। पर्वतीय जिलों में स्थानीय भवन, तकनीक और पारंपरिक निर्माण सामग्री के उपयोग को बढ़ावा देने पर भी सहमति बनी।
आकाशवाणी देहरादून के लिये समाचार कक्ष से अमित सुन्द्रियाल

आदेश

सर्वोच्च न्यायालय ने विश्वविद्यालय अनुदान आयोग– यूजीसी के उच्च शिक्षा संस्थानों में समानता सर्वधन नियम–2026 को स्थगित करने का आदेश दिया। न्यायालय ने नियमों पर कुछ आपत्तियां व्यक्त कीं, जिन्हें सामान्य वर्ग के प्रति भेदभावपूर्ण बताया गया। न्यायालय ने सुझाव दिया कि प्रतिष्ठित न्यायविदों की एक समिति द्वारा नियमों की समीक्षा की जानी चाहिए। मामले की अगली सुनवाई 19 मार्च को होगी।

समग्र शिक्षा

समग्र शिक्षा के अंतर्गत प्रदेश के पाँच सौ चवालीस नए विद्यालयों में व्यावसायिक शिक्षा संचालित करने की केंद्र सरकार ने अनुमति प्रदान कर दी है। इन विद्यालयों में छात्रों को पारंपरिक विषयों के साथ–साथ कृषि, ऑटोमोबाइल, सौंदर्य एवं स्वास्थ्य, इलेक्ट्रॉनिक्स एवं हार्डवेयर, सूचना प्रौद्योगिकी, नलसज्जा, खुदरा व्यापार तथा पर्यटन एवं आतिथ्य जैसे आठ व्यावसायिक क्षेत्रों में प्रशिक्षण दिया जाएगा।

विद्यालयी शिक्षा मंत्री डॉ. धन सिंह रावत ने बताया कि छात्रों को राष्ट्रीय कौशल योग्यता ढाँचे के अंतर्गत स्तर–तीन एवं चार के दक्षता प्रमाण पत्र प्रदान किए जाएंगे। इसके लिए 548 प्रयोगशालाएँ स्थापित की जा चुकी हैं तथा निर्धारित मानकों के अनुरूप अनुभवी प्रशिक्षकों की नियुक्ति की जा रही है।

वर्चुअल बैठक

प्रदेश के सभी सरकारी अस्पतालों को सरकारी अस्पताल सूचना प्रबंधन प्रणाली–एच.आई.एम.एस, को प्राथमिकता के साथ लागू करने के निर्देश दिए गए हैं। साथ ही प्रत्येक ज़िले में एबीडीएम के तहत एक मॉडल अस्पताल विकसित करने को कहा गया है।

देहरादून से वर्चुअल बैठक के माध्यम से राज्य स्वास्थ्य प्राधिकरण उत्तराखंड की मुख्य कार्यकारी अधिकारी और आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन की स्टेट मिशन निदेशक रीना जोशी ने सभी जिलों के मुख्य चिकित्सा अधिकारियों और उपमुख्य चिकित्सा अधिकारियों को ये निर्देश दिए। उन्होंने बताया कि केंद्र के दिशा–निर्देशों के अनुसार एचआईएमएस को मिशन मोड में लागू किया जाना है। उन्होंने सभी अस्पतालों में मरीजों का क्यूआर कोड के माध्यम से पंजीकरण और उनके स्वास्थ्य रिकॉर्ड को डिजिटल रूप से लिंक करने की व्यवस्था सुनिश्चित करने पर जोर दिया।

उन्होंने प्रदेश के सभी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों को आयुष्मान योजना में इंपैनल करने का कार्य भी प्राथमिकता से पूरा करने के निर्देश दिए।

पहल

पौड़ी गढ़वाल ज़िले के विकासखंड बीरोंखाल की ग्राम पंचायत नौगांव सोलर ऊर्जा के माध्यम से सतत विकास की दिशा में एक उदाहरण के रूप में सामने आई है। आत्मनिर्भर उत्तराखंड के विजन के तहत गांव में सोलर ऊर्जा से प्रकाश व्यवस्था को मजबूत किया गया है, जिससे रात्रिकालीन सुरक्षा और सुविधाओं में सुधार हुआ है।

ग्राम पंचायत भवन की छत पर तीन किलोवाट क्षमता का सोलर प्लांट स्थापित किया गया है, जिससे प्रतिदिन लगभग 16 यूनिट स्वच्छ ऊर्जा का उत्पादन हो रहा है। इस ऊर्जा से गांव में 40 सोलर स्ट्रीट लाइटें

संचालित की जा रही हैं, जिससे प्रमुख मार्गों, सार्वजनिक स्थलों और आवासीय क्षेत्रों में प्रकाश व्यवस्था सुनिश्चित हुई है। इससे पहले गांव के कई रास्ते रात में अंधेरे में रहते थे।

ग्राम प्रधान ओमपाल सिंह ने बताया कि गांव में करीब 70 परिवार करते हैं और सोलर स्ट्रीट लाइटों से बिजली खर्च में कमी के साथ–साथ रात्रि में आवागमन भी आसान हुआ है।

जिलाधिकारी स्वाति एस. भदौरिया का कहना है कि ऐसे सफल मॉडलों को अन्य ग्राम पंचायतों में भी अपनाने का प्रयास किया जाएगा।

और एक नजर आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों पर

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के नए नियमों पर सर्वोच्च न्यायालय ने रोक लगा दी है। हिन्दुस्तान समाचार पत्र लिखता है – कोर्ट ने कहा, शिक्षण संस्थानों में इन्हें लागू किया तो खतरनाक परिणाम होंगे। अमर उजाला लिखता है – यूजीसी के नए नियम विभाजनकारी, अस्पष्ट दुरुपयोग की भी आशंका।

उत्तराखंड सरकार ने मंत्रियों के यात्रा भत्ते में बढ़ोतरी की है। इस खबर पर नवोदय टाइम्स लिखता है – मंत्रियों के यात्रा भत्ता में 30 हजार की बढ़ोत्तरी।

यमुनोत्री धाम में भी गैर हिन्दुओं के प्रवेश पर पाबंदी होगी। इस खबर को अमर उजाला ने प्रमुखता से प्रकाशित किया है। समाचार पत्र लिखता है– अब यमुनोत्री धाम में भी गैर सनातनियों के प्रवेश पर रोक।

प्रदेश में प्रधानमंत्री आवास योजना में तेजी आएगी। इस खबर पर दैनिक जागरण लिखता है– उत्तराखंड में आवास और शहरी विकास को रफ्तार देगा हडको।